THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI G. VENKATSWAMY) : (a) and (b). The subject of payment of wages of the tea garden labourers falls in the State sphere.

Assistance to Bangladesh Refugees

9036. SHRI R. N. BARMAN :
SHRI B. K. DASCHOWDHURY :
Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the amount of loan offered to the displaced persons of ersthwhile East Pakistan now Bangladesh, State-wise;

(b) the amount of loan along with interest repaid by those displaced persons, State-wise;

(c) the directions by Central Government to State Government concerned to realise the amount of loans due from the displaced persons; and

(d) the amount of loan given to those displaced persons for house building and other purposes?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI RAGHUNATHA REDDY) : (a) and (b). A statement indicating the amount of loan given to the States for relending to the displaced persons from erstwhile East Pakistan and amount of loan with interest thereon repaid State-wise, is attached.

(c) A Remission Scheme was sanctioned in May, 1964 in respect of loans advanced by the State Governments from funds placed at their disposal by the Central Government to old migrants from former East Pakistan upto 31-3-1964. The Scheme excluded a few categories of loans advanced to comparatively well-to-do persons. Under this Scheme, the first Rs. 1,000 of the total loan burden of a migrant family are remitted in each case and out of the balance, if any, the amount in excess of Rs. 2,000 is also remitted. The liability of a migrant family thus does not exceed Rs. 2,000.

Since the introduction of this scheme in May, 1964 loans aggregating Rs. 22.12 crores have been remitted. The State-wise break-up of the amount remitted is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-4952/73]

As regards recovery of loans, the State Governments have been advised to ensure that while no efforts are spared in recovery of loans from loanees who are in a position to repay, a procedure has been prescribed to avoid coercive measures which may render the loanees destitute.

(d) Loans are disbursed by the State Governments under the Schemes approved by the Government of India and they are responsible for the maintenance of the detailed accounts of the loans. Information in respect of loans given for House Building and other purposes has been called for from the State Governments and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Target of Steel Production during 1973-74

9037. SHRI R. N. BARMAN :
SHRI VARKEY GEORGE :
Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the State-wise targets of production of steel plants during 1973-74 under the Steel Authority of India;

(b) whether the prices of steel will decrease consequent upon the rise in production in steel plants; and

(c) if so, the main features thereof, and, if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUBODH HANSDA) : (a) The following table shows the targets of production for 1973-74 in terms of steel ingots of the integrated mild steel plants under the Steel Authority of India.

Plant	('000 tonnes) Steel Ingots
Bhilai Steel Plant—Madhya Pradesh	2,250
Durgapur Steel Plant—West Bengal	1,000
Rourkela Steel Plant—Orissa	1,300
Bokaro Steel Plant—Bihar	340

(b) and (c). The prices of steel produced by these plants are regulated and there is no question therefore of an automatic decrease or increase in prices

झुंझनू जिला (राजस्थान) का भू-गर्भीय सर्वेक्षण

9038 श्री शिवनाथ सिंह क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के नबेरी ग्राम में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग का कैम्प कब से चल रहा है और अब तक इस कार्य मे क्या प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1969–70 के क्षेत्र काल के दौरान नागोरी-पोच क्षेत्र के भूवैज्ञानिक अन्वेषण आरम्भ किए। तथापि, क्षेत्र मे परीक्षण व्यधन सितम्बर, 1970 के दौरान आरम्भ हुए। क्षेत्र मे किए गए कार्य की कुल प्रमात्रा में 1 1000 मापमान पर 1 00 वर्ग किलो मीटर 650 भूरासायनिक नमूने का संकलन, 0 68 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र पर भूभौतिकीय सर्वेक्षण और सात बोर छिद्रों में 1389 43 मीटर का परीक्षण व्यधन सम्मिलित है। अभी तक किए गए कार्य ने उपदर्शित किया है कि संभाव्य खनिजीकृत क्षेत्र की सीमा नागोरी खंड में 2 8 कि० मीटर और पोंक खण्ड मे 0 5 कि० मीटर की अनुदैर्घ्य लम्बाई है। नागोरी खण्ड में परीक्षण व्यधन ने व्यधन छिद्रो की ओर 80 00 मीटर और 83 00 मीटर के बीच तीन मीटर की लम्बाई मे लम्बी पट्टियो और विकीर्णनों के रूप में स्थानीय ताम्र की विद्यमानता उद्घाटित की है। इस क्षेत्र के रासायनिक विश्लेषण के परिणाम अपेक्षित हैं। तथापि, स्थानीय ताम्र की विद्यमानता गहराई में प्रारम्भिक सल्फाइड क्षेत्र की उपस्थिति उपदर्शित करती है जिसके लिए गहन व्यधन प्रगति में है। पोंक खंड में व्यधन ने 200 मीटर की अधिक गहराई में आक्सीकृत क्षेत्र की विद्यमानता उपदर्शित की है जो गहराई में प्रारम्भिक सल्फाइड क्षेत्र मे समागम के लिए गहन व्यधन को प्रतिपादित करती है।

कल्याण आरोग्य सदन, राजस्थान को मोटर गाड़ियां देना

9039 श्री शिवनाथ सिंह क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान के सीकर जिले के कल्याण आरोग्य सदन (टी० बी० अस्पताल) को मार्च, 1973 तक कितनी मोटर गाड़िया 'डिफेंस डिस्पोजल" से दी गई हैं और ये गाड़िया किन शर्तों पर दी गई हैं, और

(ख) क्या किसी निश्चित अवधि से पूर्व उक्त आरोग्य सदन इन गाड़िया को नहीं बेच सकता था और यदि हां, तो क्या इस शर्त का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) और (ख) राजस्थान के सीकर जिले मे कल्याण आरोग्य सदन को मार्च, 1973 तक केवल आठ मोटर गाड़िया 'डिफेंस डिस्पोजल स्टाक' से दी गई हैं। इन मोटर गाड़ियो के देने के लिए ये शर्तें थी कि इन्हें खरीदने की तारीख से पांच वर्षों के अन्दर पुन बेचा नहीं जाएगा और यह मोटर गाड़ियां संगठन के अपने वास्तविक उपयोग के लिए चाहिए और इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग के लिए नहीं। तथापि, संगठन को एक मोटर गाड़ी, एक विशेष मामले के रूप मे अवधि की समाप्ति से पूर्व बेचने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि इसका रख-रखाव किफायती नहीं था।